

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2013/फाल्गुन 14, 1934

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 287

No. 40]

DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2013/PHALGUNA 14, 1934

[N.C.T.D. No. 287

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मार्च, 2013

(हज समिती अधिनियम, 2002 की धारा 21(3) के अंतर्गत प्रकाशित)

सं. एफ.-1(हज)/एडीएम(मु.)/99/पार्ट.फाईल/317.—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या :
एफ.-1(हज)/एडीएम(मु.)/99/पार्ट.फाईल/87 दिनांक 21-1-2013
के द्वारा दिल्ली राज्य हज समिति के अधिनियम, 2002 (2002 के
35) की धारा के अंतर्गत सदस्यों को नियुक्त किया गया है।

हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 21(1) के अंतर्गत
दिल्ली राज्य हज समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठक दिनांक
28-1-2013 को सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में की गयी।
जिसमें डॉ. परवेज मियां को सर्वसम्मति से दिल्ली राज्य हज कमेटी
का अध्यक्ष निर्वाचित चुना गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
धर्म पाल, सचिव

REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 5th March, 2013

(Published under Section 21(3) of Haj Committee Act, 2002)

No. F. 1(Haj)/Adm./HQ/99/Pt.file/317.—The members
of the Delhi State Haj Committee constituted under the

provisions of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002)
were notified vide Revenue Department Notification No.
F. 1(Haj)/Adm./HQ/99/Pt. file/87 dated January 21, 2013.

In terms of Section 21(1) of the Haj Committee Act,
2002, a meeting of the members of the newly constituted
Delhi State Haj Committee was held on January 28, 2013
under the Chairmanship of the Secretary (Revenue) and in
the said meeting, Dr. Parvez Mian, was elected unanimously
and unopposed as the Chairman of the Delhi State Haj
Committee.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
DHARAM PAL, Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मार्च, 2013

सं. फा. 5(54)/नीति-II/वैट/2012-13/1331-1343.—

जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16-1-2013 के पत्र
संख्या डी-2/451/12/44/2007 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार को सूचित किया है कि यूरोपीय समुदाय (यूरोपीय
आयोग) के प्रतिनिधिमंडल का नाम लिबसन सन्धि संशोधन के
अनुसार बदल कर "यूरोपीय संघ" कर दिया गया है, जो 13 दिसम्बर,
2007 को हस्ताक्षरित की गयी थी और 1 दिसम्बर, 2007 को प्रवृत्त
हुई थी और जबकि शासकीय खरीद के संबंध में मूल्य संबंधित कर

की छूट/धन वापसी के लिये इस समय सुविधाएं संशोधन पूर्व यूरोपीय आयोग के नाम पर उपलब्ध है।

अतः अब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ।

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की छठी अनुसूची के भाग-ख पर प्रविष्टि संख्या 13 पर "यूरोपीय आयोग" के स्थान पर नए शब्द "यूरोपीय संघ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रशान्त गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 5th March, 2013

No. F. 5(54)/Policy-II/VAT/2012-13/1331-1343.—

Whereas the Ministry of External Affairs, Government of

India vide letter No. D-II/451/12(44)/2007 dated 16-1-2013 has informed to the Government of National Capital Territory of Delhi that name of delegation of the Commission of the European Communities (European Commission) has been changed to the delegation of the European Union as per the treaty of Lisbon amendment which was signed on 13th December, 2007 and which entered into force on 1st December, 2009. And whereas, presently facilities for exemption/refund of VAT in respect of official purchase is available to the pre-revised name European Commission.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), I, hereby make the following amendments in the sixth schedule of the said Act, namely :

AMENDMENTS

In the Sixth Schedule of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), in the entry at Sl. No. 13 in part-B "European Commission" shall be substituted by the new word "European Union".

PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax